

प्रेषक,

टी० के० पन्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तरांचल शासन।
सेवामे,
मुख्य अभियन्ता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

विषय:- वित्तीय वर्ष 2006-07 में 10(दस) कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति
तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये 10 कार्यों के रूपये 2025.72 लाख की लागत के आगणनों पर टी.ए.सी. द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि रूपये 1776.60 लाख (रूपये सत्रह करोड़ छिहतर लाख साठ हजार मात्र) की धनराशि की लागत के आगणन की उनके समुख अंकित संलग्न विवरणानुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य प्रारम्भ करने हेतु प्रत्येक कार्य के लिये उनके समुख कालम-06 में अंकित विवरणानुसार कुल रु 0.10 हजार (रु० १० हजार मात्र) की धनराशि की वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006-07 में व्यय की भी श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बंजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन भूमि एवं निजी भूमि आदि की कार्यवाही की जाय, तथा भूमि का भुगतान नियमानुसार प्रथम वरीयता के आधार पर किया जाय एवं भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

2. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

3. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

4. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन विभाग की स्वीकृति जिन कार्यों में आवश्यक हो, पाप्त करके ही धनराशि का आहरण किया जायेगा।

5. एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

6. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

7. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भौति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा ले। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

8. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

9. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

10. कार्यदायी संस्थाओं का निर्धारण वित्त अनुभाग-1 द्वारा निर्गत शा०सं०-452/XXVII(1)/2005 दिनांक 05 अप्रैल 2005 एवं उनके द्वारा समय-2 निर्गत आदेशों के अनुसार ही किया जायेगा।

मुद्रण नं - 10
मुद्रण नं - 5330
पृष्ठा No. 4C
पृष्ठा No. 80/9/20
क्रमांक 19 सितम्बर, 2006

32/1
25/9/6

25 SEP 2006

130-14-2006-07

5 copies

(5)

2.20

(2)

(6)

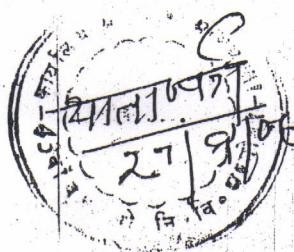
कायालिय मुठ्य अभियन्ता कु.दे. ॥
लो. नि. वि. अल्पोडा

पत्रांक 3241/516 याता. -कु. /06 ,

दिनांक: 26/9/2006,

प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता 43वाँ बृत्त, लो. नि. वि. अल्पोडा को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि बजट वर्ग क्षेत्रीय कायालिय लो. नि. वि. अल्पोडा ।



2837
2838

महाराष्ट्र अभियन्ता,
43वाँ बृत्त, लो. नि. वि. अल्पोडा.

मुठ्य अभियन्ता कु.दे.
लो. नि. वि. अल्पोडा

- (1) प्रतिलिपि उल्लेखकों को प्रति उत्ति
को धर्मानि कायालिय अभियन्ता निरुद्ध द्वा नि
रामिति को कायालिय कायालिय कायालिय
प्रेषित ।
- (2) प्रति उल्लेखकों के लिए को प्रा
मातामात (व) का ।

कायालिय मुठ्य अभियन्ता,
43वाँ बृत्त, लो. नि. वि. अल्पोडा. 26/9

छायाप्रति सत्यापित

सहायक अधिकारी
प्राप्ति कुण्ड लो. नि. वि.
रामाखरत

11. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सभी योजनाओं हेतु भूमि का अर्जन कर के कब्जा लेने के बाद ही धनराशि का आहरण किया जायेगा और यदि कब्जा प्राप्त नहीं होता है तो उस योजना हेतु धनराशि का आहरण नहीं किया जायेगा।

12. यदि उक्त कार्यों में से किसी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को सर्वप्रिय कर दी जायेगी।

13. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुरितका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने अनुपालन किया जाय। यदि टेण्डर करने में कार्य प्रशासकीय स्वीकृति की लागत से कम लागत पर पूर्ण होता है तो ऐसे समस्त बचतों को प्रचलित वित्तीय नियमों का अनुपालन कर राजकीय कोष में जमा कर दिया जायेगा।

14. आगामी किस्त तब ही अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय / भौतिक प्रगति विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया जाय। उक्त धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरान्त ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी।

15. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

16. इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006-07 के आय व्ययक में लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या-22 लेखाशीर्षक-5054 सङ्कों तथा सेतुओं फर पूँजीगत परिव्यय -04 जिला तथा अन्य सङ्को-आयोजनागत-800-अन्य व्यय -03 राज्य सेक्टर -02 नया निर्माण कार्य-24 बहुत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

17. यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-यू.ओ.-574/XXVII(2)/2006 दिनांक 18 सितम्बर, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:- 10 कार्यों की सूची।

भवदीय,

(टी० के० पन्त)
संयुक्त सचिव।

संख्या- २४९।
(१) / ११-२/०६, तददिनांक |

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
2. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोर्टर्स बिलिंग, माजरा देहरादून।
3. आयुक्त कुमांपू मण्डल, नैनीताल।
4. जिलाधिकारी / कोषाधिकारी अल्मोड़ा।
5. मुख्य अभियन्ता, कुमांपू क्षेत्र, लो.नि.वि., अल्मोड़ा।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तरांचल, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तरांचल शासन।
9. लोक निर्माण अनुभाग-1/3 उत्तरांचल शासन।
10. गार्ड बुक। मो. ५३४०/८८८८०८/३०/६/०८

छायाप्रति सत्यापित

सहायक दिग्गज
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
रानीखत

आज्ञा से-

(टी० के० पन्त)
संयुक्त सचिव।

उपलिपि निम्न लिखित का संचालन
एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु किया जायेगा।
① संवृत्ति सं० ३५४०/८८८८०८/३०/६/०८
लो.नि.वि. कोषाधिकारी अल्मोड़ा

② कमिश्न अल्मोड़ा (लो.) पा० ५०८० लिपि २
२०११

(6)

22P

(8)

शासनादेश संख्या- 249) ।।।(2) / 06-36(प्रा.आ.) / 06 दिनांक / १५ सितम्बर, 2006 का संलग्नक
(धनराशि लाख रुपये में)

क्र० सं०	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी. में)	अनुमानित लागत	टी.ए.सी. वित्त द्वारा आंकित राशि	वित्तीय वर्ष 2006- 07 में व्यय की स्वीकृति
1	2	3	4	5	6
✓ 1.	अल्मोड़ा में हरड़ा-भिकियासैण हॉवा० मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करने एवं अवशेष भाग का नव निर्माण	8.00	265.42	189.60	0.01
✓ 2.	Ric 2. गुरणखेत-सूरी मोटर मार्ग का नव निर्माण	5.00	99.20	89.00	0.01
✓ 3.	सौगढ़-पन्तगाँव मोटर मार्ग का डामरीकरण	6.800	128.20	128.20	0.01
✓ 4.	सल्ट में रापड़-जीनापानी-मझेड़ा मोटर मार्ग का नव निर्माण	18.00	439.50	409.50	0.01
✓ 5.	अल्मोड़ा में सरपटा-चनुली-कोटा बासोट मोटर मार्ग	9.00	173.70	160.20	0.01
✓ 6.	विनायक-रिखाड़-कोटियाग मोटर मार्ग	7.00	142.24	124.60	0.01
✓ 7.	हरड़ा-भिकियासैण मोटर मार्ग का सुधार एवं डामरीकरण	4.00	68.40	68.40	0.01
✓ 8.	सल्ट के अन्तर्गत झीमार-भैसखेत-डढोली मोटर मार्ग	10.00	200.5	178.00	0.01
✓ 9.	सल्ट के अन्तर्गत कारगिल शहीद आनन्द सिंह रावत के ग्राम मिवाईपानी तक स्वीकृत मोटर मार्ग का लिलितपुर-खाटली तक विस्तार	6.00	121.80	106.80	0.01
✓ 10.	मरचूला-स्याल्दे-देघाट मोटर मार्ग के पैठणा से नौला तक डामरीकरण एवं सुधार	22.00	386.76	322.30	0.01
कुल योग			2025.72	1776.60	0.10

(रुपये दस हजार मात्र)

(टी० के पन्त)

संयुक्त सचिव।

छायाप्रति सत्यापित

सहायक अधिकारी
आन्तरीय स्पष्टीकरण विभाग
राजनीतिक

परिशिष्ठ

(दिविय नियम-6)

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की
धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

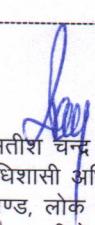
भाग-1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

1	A.	परियोजना विवरण				
	A.	अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का विवरण –	जनपद अल्मोड़ा में सरपटा-चनुली-कोटा-बासोट मोटर मार्ग का नव निर्माण। लम्बाई – 6.50 किमी। आपेक्षित वन भूमि शून्य है। सिविल एवं सोयम भूमि 0.250 है। वन पंचायत – 0.287 है।			
	B.	1.50.000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आसपास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप/डिजिटल मैप	संलग्न है।			
	C.	परियोजना की लागत—	160.20 लाख।			
	D.	वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य—	स्थानीय जनता को यातायात की सुविधा हेतु।			
	E.	लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)–	संलग्न है।			
	F.	रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना हैं—	निर्माण कार्य से स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा।			
2		कुल आपेक्षित भूमि उद्देश्यवार विवरण—	आपेक्षित वनभूमि	राज्य वन भूमि	वन पंचायत भूमि	कुल भूमि
			—	0.250 है।	0.287 है।	0.537 है।
3		परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण यदि कोई है—	आवश्यकता नहीं।			
	A.	परिवारों की संख्या—	आवश्यकता नहीं।			
	B.	अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या—	आवश्यकता नहीं।			
	C.	पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)—	आवश्यकता नहीं।			
4		क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है। (हाँ/नहीं)	नहीं।			
5		प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और/या दण्डस्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की बचनबद्धता (बचनबद्धता संलग्न की जाये)	सभी प्रमाण-पत्र प्रस्ताव पर संलग्न है। वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।			
6		निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का व्यौरा।	संलग्न है।			

दिनांक— 02.12.2014

स्थान— रानीखेत

(सतीश चन्द्र आर्य)
 अधिशासी अभियन्ता,
 प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,

 रानीखेत